'सभी जर्जर सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत करायें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पिपलोदी हादसे के बाद बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये

जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित, संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से हम सब दुखी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और उपयोग के लिए असुरक्षित पाए जाने पर भवनों को तुरंत खाली करवाया जाए और प्रभावितों का अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर उनके लिए अस्थायी कक्षाओं का संचालन सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर किया जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट घोषणाएं की थी। साथ ही, बजट 2025-26 में भी भवनविहीन व जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 375 करोड़ रूपये का

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि असुरक्षित पाये जाने वाले भवनों को तुरंत खाली करवा कर प्रभावितों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाना चाहिये। गत दो बजट में राज्य सरकार ने विद्यालयों के भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए 625 करोड़ रूपयों का आवंटन किया है।**

प्रावधान किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक के दौरान, पीपलोदी हादसे पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित, विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे तथा वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्तगण, जिला कलक्टर्स एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी जुड़े।

सरकार ने 25 ओटीटी चैनल बैन किए

नई दिल्ली, 25 जुलाई। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट में बढ़ रही अश्लीलता को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कथित तौर पर अश्लीलसामग्री दिखाने के लिए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनके संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। इनमें उल्लू, एल्ट, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अलग-अलग जांच एजेंसियों से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद यह फैसला लिया है।

- **इनमें ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स, ड्रीम फिल्म्स आदि बड़े नाम शामल हैं। आरोप है कि इन पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही थी।**

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य अश्लील और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के दिखाए जाने पर रोक लगाना है।

प्रतिबंधित एप्लिकेशन की लिस्ट में प्राइम प्ले, हंटर्स, ड्रीम फिल्म्स, रंगीन और नियोनएक्स वीआईपी भी शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म की अक्सर अपने अश्लील कंटेंट और एडल्ट सीरीज को लेकर आलोचना की जाती रही है, जिसके चलते ये प्लेटफॉर्म अक्सर निशाने पर भी रहते हैं।

करौली में मारुति वैन-पिकअप भिड़ंत में चार महिलाओं की मौत

दुर्घटना में चार मृतक व 14 घायल जाटव परिवार के तथा एक ही कुटुंब के थे

करौली, 25 जुलाई (निंस.)। ईको वैन और एक पिकअप की आमने-सामने की टक्कर में चार महिलाओं की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हादसे में 11 महिलाएं, तीन पुरुष और तीन बालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति को उपचार के लिए जयपुर अस्पताल के लिए रैफर किया।

हिण्डौन क्षेत्र के बेड़ा वनकी गांव और मुड़ियांकापुरा निवासी एक वैन में करीब 17 महिला पुरुष और बच्चे करौली के पास माची गांव में एक रिश्तेदार महिला की मृत्यु के बाद तीए की बैठक में आए थे। वापस लौटते समय, करौली हिण्डौन सड़क मार्ग पर गुडला गांव के पास सड़क पर सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर को देख घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर

- **हिण्डौन के बेड़ा वनकी गाँव व मुडियांकापुरा के 17 लोग, महिला, पुरुष व बच्चे, एक वैन में करौली के पास माची गाँव में तीये की बैठक में शामिल होने गये थे। लौटते समय गुड़ला गाँव के पास पिकअप से सीधी भिड़ंत हो गई।**

पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से लोगों की मदद एवं निजी वाहनों से घायलों को करौली सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जिनमें से चार महिलाएं गुड्डी पत्नी विनोद 35, कमला पत्नी रेवती 40, शकुंतला पत्नी कजोड़ी जाटव 60 व मछला पत्नी जगदीश 40 को ड्यूटी डॉ. ने मृत घोषित कर दिया। इनके अलावा, वाहन चालक दरव सिंह 50 गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया । बाद में शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिये। घटना की गंभीरता को देखते हुए, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, सदर थाना अधिकारी रामदीन शर्मा पुलिस बल के साथ सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। मृतक और घायल एक जाति विशेष जाटव परिवार के और एक ही कुटुंब के थे। इधर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामकेश मीणा को घायलों को अच्छा उपचार देने के निर्देश दिए।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धनखड़ द्वारा विपक्ष के प्रस्ताव का उल्लेख किए जाने को उनके चौंकाने वाले इस्तीफे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति ने, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, पद छोड़ दिया। सोमवार को उनके इस्तीफे के बाद सरकारी सूत्रों ने कहा कि यदि धनखड़ ने प्रस्ताव स्वीकार करने के अपने इरादे के बारे में सरकार को पहले ही बता दिया होता, तो सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये होते, जिससे जनता की नजर में भाजपा को इस महाभियोग की पहल करने का श्रेय मिल जाता। इस बीच, चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, भारत को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।

सोमवार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रणनीति बदल दी है, वह अभी तक बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित कर रहा था और अब, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को विदेश यात्रा से लौटने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान देने की योजना बना रहा है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर और परिसर में, दोनों जगह जारी हैं।

इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले दूसरे प्र.मंत्री बने मोदी

मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं

नई दिल्ली, 25 जुलाई। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभी तक लगातार सबसे लंबे समय तक (16 वर्ष 286 दिन) प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू के पास है।

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लेंगे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री रही थीं। अगर राज्य और केंद्र में सरकार का नेतृत्व करने की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक अलग रिकॉर्ड है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।

- **अगर सरकार का नेतृत्व करने की बात की जाए तो मोदी के नाम एक विशेष रिकॉर्ड है। वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रुप में 24 साल तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।**
- **इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी और मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर चुके हैं।**

नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वह सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले और प्रधानमंत्री पद पर दो कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। उनके नाम लगातार दो बार निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानंत्री होने का रिकॉर्ड भी है।

पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता भी हैं। वह इंदिरा गांधी (1971) के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। पंडित नेहरू के अलावा वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार तीन आम चुनाव जीते हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरु

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है और उनकी सहायता के लिए राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को

- **राज्यसभा महासचिव बनाये गये निर्वाचन अधिकारी**

सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया है। आयोग ने इस संबंध में गजट अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। आयोग ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस चुनाव के संबंध में निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

मानवाधिकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से बच्चे दुर्घटना के शिकार हो गए। ऐसे में यह जरूरी है कि घटना के दोषियों को सजा मिले ओर पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति दी जाए।

सिंहस्थ कुम्भ के लिए नासिक के समीपवर्ती 5 रेल्वे स्टेशन विकसित होंगे

सिंहस्थ कुम्भ में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के मद्देनजर, रेलवे 1.011 करोड़ रुपये की लागत से आसपास के पांच रेलवे स्टेशनों को विकसित करेगा।

जिन स्टेशनों को विकसित किया जाना है, उनमें नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ I, खेरवाड़ी और कसबे सुकेणे शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, भुसावल मंडल के मंडल रेल अधिकारी (डीआरएम) और अन्य अधिकारियों ने मंत्रियों तथा रेलवे बोर्ड को इसकी योजना और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

वैष्णव ने अधिकारियों से महाकुंभ 2025 के अनुभव से प्राप्त सर्वोत्तम

- **रेल्वे एक राउण्डट्रिप सर्किट ट्रेन भी चलाएगा, जो तीन ज्योतिर्लिंगों, त्रयम्बकेश्वर, ओकांरेश्वर व घृष्णेश्वर को आपस में जोड़ेगी।**

कार्यप्रणालियों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को नासिक के सभी निकटवर्ती स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधायें विकसित करने की सलाह दी।

इसके अलावा, सभी पांचों स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं के विकास की योजना है। इनमें कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म, पानी की टंकियां, नये शौचालय और वाटरप्रूफ होल्डिंग एरिया शामिल हैं। सर्कुलेटिंग एरिया, रास्ते, प्रवेश/निकास मार्ग और यात्री सूचना प्रणालियों को भी उन्नत करने की योजना है। सिंहस्थ कुंभ में तीन करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए रेलवे बहुत अधिक संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। एक राउंड-ट्रिप विशेष सर्किट ट्रेन भी चलायी जाएगी। यह तीन ज्योतिर्लिंगों- त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी।

तीर्थयात्रियों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रमुख स्टेशन पर बड़े होल्डिंग एरिया विकसित किये जा रहे हैं। एक केन्द्रीयकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रभावी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और पूर्वानुमानित समय-निर्धारण के लिए एआई उपकरणों से सुसज्जित होगा। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे, तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

कोचिंग सेंटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए 15 निर्देश

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण कराने सहित, 15 बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के अभ्यर्थी 17 वर्षीय एक छात्र की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।

विशाखापत्तनम में छात्र की अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह दुखद घटना जुलाई में विशाखापत्तनम स्थित आकाश-बायजू संस्थान में हुई थी।

पीठ ने मृतक के पिता सुकदेब साहा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने इसके अलावा केन्द्र सरकार को 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल कर अनुपालन के संबंध में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

"उदयपुर फाइल्स" को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जाकर बहस करें। हमने पहले ही 12 दिन खो दिए हैं। प्राधिकरण ने भी आदेश पारित कर दिया है।"

इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, "12 दिन कोई नुकसान नहीं, जितनी पब्लिसिटी, उतना फिल्म को फायदा।"

हालाँकि भाटिया ने मदनी का हवाला देते हुए कहा, ऐसे लोग हमेशा 'सुपर सेंसर' की तरह काम करते हैं और फिल्म रिलीज़ पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं।

"1200 स्क्रीन बुक थीं, पैसा निवेश हो चुका है। हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं? कि किसी की भावनाएं आहत हों और सीधे कोर्ट से स्टे ले आएं?"

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया, बल्कि हाईकोर्ट को विवेकानुसार निर्णय लेने की छूट दी।

कोर्ट ने आदेश में कहा: "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। हाईकोर्ट स्वतंत्र है, जो भी आदेश उचित समझे, पारित कर सकता है।"

धनखड़ को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धनखड़ को उनके इस्तीफे के कुछ दिनों के बाद यह निमंत्रण दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है।(विपक्षी दलों की ओर से राज्यसभा के वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि 74 वर्षीय धनखड़ को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण तक देने का मौका नहीं मिला। इसी मुद्दे को और जोर देने के लिए विपक्षी दलों ने एक विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन किया है।

गाज़ियाबाद की जूलरी शॉप में करोड़ों की लूट

गाजियाबाद, 25 जुलाई। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय वेश में आए हथियारबंद बदमाशों ने गुरुवार को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गन प्वाइंट पर लाखों के गहने और नगदी लूट ली। लूटपाट की यह घटना ज्वेलरी शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

बृज विहार में कृष्ण कुमार वर्मा की मानसी ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान है। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दो बदमाश बाइक से दुकान पर पहुंचे। उन्होंने स्विगी और ब्लिंकिट जैसी डिलीवरी कंपनियों की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जब वे दुकान में घुसे, तब दुकान में कृष्ण कुमार का बेटा शुभम वर्मा और एक कर्मचारी मौजूद था। शुभम वॉशरूम गया था और कर्मचारी काउंटर पर बैठा था। बदमाशों ने अंदर घुसते ही कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। इसी दौरान शुभम वापस आ गया। बदमाशों ने उसे भी पिस्टल दिखाकर डराया और मारपीट की। इसके बाद, दोनों बदमाशों ने दुकान में रखे करीब 20 किलो चांदी,

- **लुटेरे स्विगी व ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय बनकर दुकान में घुसे थे**
- **बदमाशों ने 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोने के आभूषण तथा 20 हजार रुपए लूटे हैं। मात्र 6 मिनट में लूटपाट कर वे बाइकों से फरार हो गए।**

125 ग्राम सोने के गहने और 20 हजार रुपये नकद दो बैगों में भर लिए। लूट के बाद बदमाश पिस्टल के दम पर शुभम और कर्मचारी को दुकान के बाहर ले गए और बाइक से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद शुभम ने तुरंत अपने पिता और पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शुभम से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक, लूट की जानकारी शाम करीब 4 बजे मिली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात सिर्फ 6 मिनट में अंजाम दी गई। जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की बाइक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि बाइक पर जो नंबर प्लेट लगी थी, वह फर्जी थी। साथ ही बदमाश दिल्ली की ओर से आए थे। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर दुकान में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। घटना का पूरा 6 मिनट का वीडियो सामने आया है, जिसे पुलिस सुराग जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर भागने लगे तो ग्रामीणों ने रोककर गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आ रही है।

बाद में, पुलिस ने लाठियां फटकारीं और लोगों को खदेड़ा। लोग पहाड़ियों पर जा चढ़े। मौके पर पुलिस का बड़ी तादाद में जाप्ता तैनात है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आने की भी सूचना थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से मनोहर थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के स्टाफ द्वारा लगातार ग्रामीणों की शिकायत को दरकिनार किया जा रहा था और ग्रामीणों के मना करने के बाद भी इमारत में बच्चों को बिठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों ने जब विरोध जताया तो स्कूल के स्टाफ ने उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी।

जानकारी के अनुसार, मामले में एक्शन लेते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मीना गर्ग, जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल लोधा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने स्कूल के स्टाफ पर कार्यवाही करके इतिश्री कर ली है, जबकि बड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा विधायक गोविंद रानीपुरिया, जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं सभी स्थानीय अधिकारियों को बार-बार स्कूल की हालत से अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सब आश्वासन ही देते रहे और यह हादसा हो गया।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मनोहर थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में हादसे में घायल बच्चों का हालचाल पूछा, भर्ती छात्रों की कुशलक्षेम पूछी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घायलों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढ़स बंधाया और सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। शिक्षा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि इलाज में कोई कमी न रह जाए और सभी आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।

विपक्ष ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए।

विपक्षी सांसद बैनर लेकर चल रहे थे जिसमें 'एसआईआर- लोकतंत्र पर वार' लिखा हुआ था। उन्होंने 'एसआईआर वापस लो' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाये।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रेनी एसआई सहित, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि पेपर लीक को लेकर व्यापक स्तर पर जांच चल रही है और अभी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

सावरकर पर बयान के मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वीर सावरकर पर विवादास्पद बयान देने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई राहत जारी रखते हुए निचली अदालत के समन पर शुक्रवार को अंतरिम रोक की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कांग्रेस नेता गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि वह इससे मामले में चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने निचली अदालत के समन पर रोक लगाने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च

- **सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के सम्मन पर अंतरिम रोक की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है।**

न्यायालय के आदेश को विशेष अनुमति याचिका के जरिए चुनौती दी है।

गांधी ने अधिवक्ता प्रसन्ना एस के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दलील दी है कि शिकायत और निचली अदालत (मजिस्ट्रेट) का आदेश धारा 153 ए और 505 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का संज्ञान आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। यह शीर्ष न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के विपरीत है। याचिका में दलील दी गई है कि उनकी (राहुल गांधी) टिप्पणियाँ एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थीं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से शत्रुता या घृणा फैलाना नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही वास्तव में उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने का एक प्रयास है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी पर लगाए गए आरोपों के संबंध जारी अदालती समन का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है।

मानव रहित यान से मिसाइल का सफल ट्रायल

हैदराबाद, 25 जुलाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज (एनओएआर) से उन्नत मानवरहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यूएलपीजीएम-वी3 पहले से विकसित यूएलपीजीएम-वी2 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। यह मिसाइल तीन प्रकार के मॉड्यूलर वॉरहेड प्रदान करती है, जिसमें एंटी-आर्मर कॉन्फ़िगरेशन भी शामिल है, जो रोल्ड होमोजीनियस आर्मर (आरएचए) और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ईआरए) से सुसज्जित आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में सक्षम है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908